

## अनुसूचति जनजात (ST) सूची में संशोधन हेतु वधियक

### प्रलिम्स के लयि:

राष्ट्रीय अनुसूचति जनजात आयोग, अनुसूचति जनजात, संवधान की पाँचवी अनुसूची, संवधान की छठी अनुसूची ।

### मेन्स के लयि:

अनुसूचति जनजातियों की सूची में शामिल करने की प्रक्रया, भारत में जनजातियों से संबंधति संवधानिक प्रावधान और पहल ।

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में 4 राज्यों - तमलिनाडु, कर्नाटक, हमिचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ में [अनुसूचति जनजात \(ST\) सूची](#) को संशोधति करने की मांग करने वाले चार वधियकों को [संवधान \(ST\) आदेश, 1950](#) में प्रस्तावति संशोधनों के माध्यम से [लोकसभा](#) में पेश कयि गया था ।

## प्रस्तावति परिवर्तन:

- वधियक का उद्देश्य:
  - तमलिनाडु की ST सूची में [नारीकोरवन और कुरुवकिकरन पहाड़ी जनजातियों](#) को शामिल करना ।
    - [लोकसमति \(1965\)](#) ने भी अपनी रिपोर्ट में उन्हें सूची में शामिल करने की सफारशि की थी ।
  - कर्नाटक की ST सूची में पहले से ही वर्गीकृत [काडू कुरुबा](#) के पर्याय के रूप में [बेट्टा-कुरुबा](#) को शामिल करना ।
  - छत्तीसगढ़ की ST सूची में पहले से वर्गीकृत भारया भूमया जनजात के लयि देवनागरी लिपि में अन्य समानार्थक शब्द जोड़ना ।
    - जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अनुसार, वे सभी एक ही जनजात का हसिा हैं, लेकिन उन्हें सूची से बाहर रखा गया था क्योंकि उनके नाम अलग-अलग हैं ।
  - सरिमोर ज़िले में ट्रांस-गरि क्षेत्र के [हट्टी समुदाय](#) को हमिचल प्रदेश की ST सूची में शामिल करना (लगभग पाँच दशकों के बाद) ।

## ST सूची में शामिल करने की प्रक्रया:

- राज्य द्वारा सफारशि:
  - जनजातियों को ST की सूची में शामिल करने की प्रक्रया संबंधति राज्य सरकारों की सफारशि से शुरू होती है, जसि बाद में जनजातीय मामलों के मंत्रालय को भेजा जाता है, जो समीक्षा करता है और अनुमोदन के लयि [भारत के महापंजीयक](#) को इसे प्रेषति करता है ।
- NCST से मंजूरी: इसके बाद सूची को अंतिम नरिणय के लयि कैबिनेट को भेजे जाने से पहले [राष्ट्रीय अनुसूचति जनजात आयोग \(National Commission for Scheduled Tribes- NCST\)](#) द्वारा मंजूरी दी जाती है ।
- राष्ट्रपति की सहमति: अंतिम नरिणय करने की शक्ति राष्ट्रपति में नहिति है ([अनुच्छेद 342](#) के तहत) ।
  - अनुसूचति जनजात में [कसि भी समुदाय को शामिल करने की प्रक्रया संवधान \(अनुसूचति जनजात\) आदेश, 1950](#) में संशोधन करने वाले वधियक को राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही प्रभावी होती है ।

## भारत में अनुसूचति जनजातियों से संबंधति प्रावधान

- परभाषा:
  - भारत का संवधान अनुसूचति जनजातियों की मान्यता के मानदंडों को परभाषति नहीं करता है । [वर्ष 1931 की जनगणना के अनुसार](#), अनुसूचति जनजातियों को "बहषिकृत" और "आशकि रूप से बहषिकृत" कषेत्रों में रहने वाली "पछिड़ी जनजातियों" के रूप में मान्यता जाना जाता है ।
  - भारत सरकार अधनियम 1935 ने पहली बार प्रांतीय वधिनसभाओं में "पछिड़ी जनजातियों" के प्रतनिधियों को शामिल कयि जाने की मांग की ।
- संवधानिक प्रावधान:

